

19 दिसंबर, 2021 करेंट अफेयर्स

1. 8वां हिंद महासागर संवाद:

आठवां हिंद महासागर संवाद 15 दिसंबर, 2021 को हाल ही में आयोजित किया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- इस संवाद की मेजबानी विदेश मंत्रालय और भारतीय विश्व मामलों की परिषद ने संयुक्त रूप से की थी।
- इस संवाद की मेजबानी “हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) सदस्य राज्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और व्यापार के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ” विषय के अंतर्गत की गई थी।

संबोधन की प्रमुख बातें:

- इस संवाद के दौरान, विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने महामारी से उबरने के लिए IORA सदस्य राज्यों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता पर ध्यान दिया।



- उन्होंने नई और उभरती प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला और इस पर सहयोग करने के लिए भारत की तत्परता की फिर से पुष्टि की।

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के बारे में:

IORA को पहले हिंद महासागर रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (IOR-ARC) और हिंद महासागर रिम इनिशिएटिव के रूप में जाना जाता था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 23 देश शामिल हैं जो हिंद महासागर के साथ सीमा साझा करते हैं। यह एक क्षेत्रीय मंच है, प्रकृति में त्रिपक्षीय है। यह सहयोग को बढ़ावा देने और उनके बीच घनिष्ठ संपर्क को बढ़ावा देने के लिए सरकार, शिक्षा और व्यवसाय के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है।

आईओआरए के सिद्धांत:

आईओआरए, आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए खुले क्षेत्रवाद के सिद्धांतों पर विशेष रूप से व्यापार सुविधा और निवेश, प्रचार और क्षेत्र के सामाजिक विकास पर आधारित है।

आईओआरए का सचिवालय

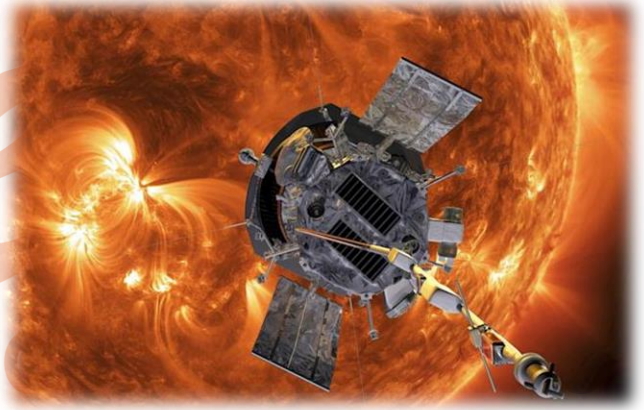
आईओआरए का समन्वय सचिवालय मॉरीशस के एबेने में स्थित है।

आईओआरए का इतिहास:

IOIRA को पहली बार मार्च 1995 में हिंद महासागर रिम पहल के रूप में स्थापित किया गया था। इसे औपचारिक रूप से मार्च 1997 में "क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का चार्टर" नामक एक बहुपक्षीय संधि के समापन के साथ शुरू किया गया था।

2. नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के कोरोना में किया प्रवेश:

हाल ही में, एक वैज्ञानिक पेपर से पता चला है कि, नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने 28 अप्रैल, 2021 को सफलतापूर्वक सूर्य के कोरोना में प्रवेश किया।



प्रमुख तथ्य:

- कोरोना, सूर्य के वायुमंडल की बाह्यतम परत है। यहां, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र, प्लाज्मा को बांधते हैं और साथ ही अशांत सौर हवाओं को इधर-उधर भागने से रोकते हैं।
- 28 अप्रैल से पहले, अंतरिक्ष यान अल्फ़वेन बिंदु से ठीक आगे उड़ रहा था।

- अल्फवेन बिंदु तब बनता है जब सौर हवाएं महत्वपूर्ण गति से अधिक हो जाती हैं और सूर्य के कोरोना और चुंबकीय क्षेत्रों से मुक्त हो जाती हैं।

पार्कर सोलर प्रोब:

पार्कर सोलर प्रोब, नासा का एक अंतरिक्ष यान है। इसे 12 अगस्त, 2018 को लॉन्च किया गया था। इसे सूर्य के बाहरी कोरोना का अवलोकन करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। यह सूर्य के केंद्र से 9.86 सौर त्रिज्या के भीतर पहुंच गया। 2025 तक, यह निकटतम दृष्टिकोण से यात्रा करेगा। यह कम सौर कोरोना में उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है।

पृष्ठभूमि

इस परियोजना की घोषणा 2009 में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से की गई थी। इस अंतरिक्ष यान को जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। यह नासा का पहला अंतरिक्ष यान है, जिसका नाम किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। इसका नाम गैर-राजनीतिक भौतिक विज्ञानी यूजीन न्यूमैन पार्कर के सम्मान में रखा गया है।

सूर्य का कोरोना:

सूर्य का कोरोना अपने चारों ओर प्लाज्मा की एक आभा है। यह बाहरी अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान कोरोना आसानी से दिखाई देता है। इसे

कोरोनोग्राफ के साथ भी देखा जा सकता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी माप के अनुसार, कोरोना में एक मजबूत आयनीकरण और 1000000 केल्विन का प्लाज्मा तापमान होता है। यह सूर्य की सतह की तुलना में बहुत अधिक गर्म होता है।

3. कैबिनेट ने 2021-26 के लिए PMKSY के कार्यान्वयन को मंजूरी दी:

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2021-26 के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के कार्यान्वयन को सहमति दी।



प्रमुख बिंदु:

- इस योजना को 93,068 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लागू किया गया था।
- सीसीईए ने राज्यों को 37,454 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी।

- पीएमकेएसवाई 2016-21 के दौरान सिंचाई के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋण के लिए 20,434.56 करोड़ की ऋण अदायगी को मंजूरी दी गई है।
- इस योजना के एक भाग के रूप में, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), वाटरशेड विकास और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) घटकों को 2021-26 के लिए बढ़ा दिया गया है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी):

- AIBP, एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे भारत सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- वर्ष 2021-26 के दौरान इस योजना के जारी रहने से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन का कुल लक्ष्य 13.88 लाख हेक्टेयर है।
- चल रही 60 परियोजनाओं को पूरा करने के अलावा, अतिरिक्त परियोजनाएं भी प्रारंभ की जा सकती हैं।
- कैबिनेट ने आदिवासी और सूखा प्रवण क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाओं के समावेश के मानदंडों में ढील दी है।

हर खेत को पानी (HKKP) के बारे में:

- इस योजना के हर खेत को पानी घटक का उद्देश्य सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेत पर भौतिक पहुंच और खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना है।

- इसके अंतर्गत जल निकायों की मरम्मत-नवीनीकरण-पुनर्स्थापना और सतही लघु सिंचाई घटकों को 4.5 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई प्रदान करने का लक्ष्य है।

वाटरशेड विकास:

- इस योजना का यह घटक मिट्टी और जल संरक्षण के लिए वर्षा सिंचित क्षेत्रों के विकास, अपवाह को रोकने, भूजल के पुनर्जनन और जल संचयन और प्रबंधन से संबंधित विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- स्वीकृत वाटरशेड विकास घटक 2021-26 के दौरान सुरक्षात्मक सिंचाई के अंतर्गत अतिरिक्त 2.5 लाख हेक्टेयर लाने के लिए 49.5 लाख हेक्टेयर वर्षा सिंचित या निम्नीकृत भूमि को कवर करेगा।

पीएमकेएसवाई के बारे में:

PMKSY योजना 2015 में शुरू की गई थी। यह एक छत्र योजना है जो विशिष्ट गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय अनुदान प्रदान करती है। इसमें दो प्रमुख घटक शामिल हैं, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)।

4. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के विवाह की आयु 21 वर्ष करने को सहमति दी:

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को सहमति दी।



पृष्ठभूमि:

अगस्त 2020 में, स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा के एक वर्ष बाद इस प्रस्ताव को सहमति दी गई थी।

विवाह के लिए वर्तमान आयु:

वर्तमान में, पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है जबकि महिलाओं के लिए यह 18 वर्ष है।

टास्क फोर्स के बारे में:

जया जेटली की अध्यक्षता में इस टास्क फोर्स का गठन जून 2020 में किया गया था। इसका गठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लड़कियों के लिए विवाह की सही आयु की फिर से जांच करने के लिए किया गया था। इसने दिसंबर 2020 में रिपोर्ट दी। इसने सिफारिश की थी कि, पहले बच्चे को जन्म देने

के समय महिलाओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इस टास्क फोर्स ने लड़कियों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की सिफारिश की। इस प्रस्ताव ने विवाह की आयु को स्वास्थ्य और सामाजिक सूचकांकों जैसे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और माताओं और बच्चों में पोषण के स्तर से भी जोड़ा।

अब किन अधिनियमों में संशोधन किया जाएगा?

इस प्रस्ताव को सहमति मिलने से सरकार नए प्रस्ताव को आकार देने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन लाएगी।

इस कदम का महत्व:

विवाह में देरी से महिलाओं, बच्चों, परिवारों और समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह महिलाओं को कुपोषण से भी बचाएगा।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

जानकारों का मानना है कि विवाह की आयु बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि:

बाल विवाह रोकने वाला कानून कार्य नहीं करता। 1978 में 18 वर्ष की विवाह की आयु तय की गई थी। हालांकि, 1990 के दशक के दौरान बाल विवाह में गिरावट शुरू हुई, जब सरकार ने बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना शुरू किया और गरीबी को कम करने की पहल की।

नए कानून से विवाहों का अपराधीकरण बढ़ेगा।

5. बाल श्रम पर तेलंगाना के नए नियम:

तेलंगाना सरकार ने केंद्र द्वारा तैयार किए गए नियमों के अनुरूप बाल श्रम के खतरे को रोकने के लिए एक संशोधित दिशानिर्देश जारी किया है।



महत्वपूर्ण तथ्य:

- राज्य सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने या जबरदस्ती करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना चाहती है।
- संशोधित मानदंडों के अनुसार, यदि कोई 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार देने का प्रयास करता है, तो उसे छः महीने से एक वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है।
- उन पर 20 हजार से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

टास्क फोर्स कमेटी के बारे में:

श्रम विभाग बाल श्रम की समस्या पर प्रभावी ढंग से निगरानी रखने और उस पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित जिला

कलेक्टर की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स समिति का भी गठन करेगा।

क्या बच्चे फिल्मों या धारावाहिकों में काम कर सकते हैं?

- संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, फिल्म निर्देशक को फिल्मों या धारावाहिकों में बच्चों को शामिल करने के लिए संबंधित कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी।
- बच्चों को केवल पांच घंटे काम करने की अनुमति होगी, जिसमें तीन घंटे के बाद एक ब्रेक होगा।
- शूटिंग के दौरान बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चालक दल के सदस्यों की आवश्यकता होती है।
- इसके अलावा, बच्चे को केवल 27 दिनों तक शूटिंग में भाग लेने की अनुमति होगी।
- यदि शूटिंग में पांच से अधिक बच्चे भाग ले रहे हैं, तो पर्यवेक्षण के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करना होगा।
- बच्चे के पारिश्रमिक का 25 % बैंक में जमा करना होगा। यह राशि बच्चे के बालिग होने के बाद दी जाएगी।

माता-पिता के लिए प्रावधान:

- यदि माता-पिता बच्चों को कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं, तो उन्हें भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। माता-पिता अपने बच्चों से सहायता ले सकते हैं, लेकिन इससे उनकी शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

- गाइडलाइंस में आगे कहा गया है कि जोखिम के कामों, रिटेल चेन और मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

स्कूल प्राचार्य के लिए दिशानिर्देश:

यदि कोई बच्चा बिना अनुमति के 30 दिनों तक स्कूल नहीं जाता है, तो स्कूल के प्रिंसिपल को संबंधित नोडल अधिकारी के ध्यान में लाना होगा।

6. पीएम मोदी ने किया अखिल भारतीय महापौरों के सम्मेलन का उद्घाटन

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में एक अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन को संबोधित और उद्घाटन किया।



प्रमुख तथ्य:

उत्तर प्रदेश के शहरी विकास विभाग द्वारा अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का आयोजन किया गया।

सम्मेलन में 100 से अधिक शहरों के महापौरों की भागीदारी देखी गयी।

तीन दिवसीय प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद महापौर सम्मेलन शुरू हुआ।

सम्मेलन का स्थान:

यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश के बड़ा लालपुर में दीन दयाल उपाध्याय-व्यापार सुविधा केंद्र (डीडीयूटीएफसी) में आयोजित किया गया।

सम्मेलन का महत्व:

यह सम्मेलन काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के कारण वाराणसी में एक महीने तक चलने वाले समारोह की शुरुआत का प्रतीक है।

प्रदर्शनी का उद्घाटन:

- इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी तीन दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
- टीएफसी परिसर में "चेंजिंग अर्बन एनवायरनमेंट" थीम के अंतर्गत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
- इसका आयोजन 17 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 तक किया गया।

- इस प्रदर्शनी में शहरी विकास में भारत सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया।
- प्रइस दर्शनी में भारत के अन्य जिलों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में की गई विशेष और उल्लेखनीय उपलब्धियों से संबंधित कार्यों को प्रदर्शित किया गया।

सम्मेलन का एजेंडा:

इस सम्मेलन के दौरान पांच महापौरों के समूह ने शहरी विकास के मुद्दों पर चर्चा की।

7. 6जी तकनीक क्या है?

संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने

हाल ही में इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित 6G बुनियादी ढांचे का उपयोग करके संचार प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी को विकसित करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसके 2023 के अंत या 2024 की शुरुआत में प्रारंभ होने की संभावना है।



प्रमुख बातें:

- हालांकि 5G अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, 6G का निर्माण शीर्ष पर होगा।
- 6G मानव, भौतिक वातावरण और आभासी वातावरण को एक साथ लाएगा।
- उदाहरण के लिए, Metaverse 5G उपयोग के मामलों में से एक है। यह पारंपरिक और साथ ही डिजिटल स्पेस को बाधित करने का वादा करता है। 6G के लॉन्च के साथ, मेटावर्स एक अंतिम मॉडल के रूप में विकसित होगा, लेकिन यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करके भौतिक दुनिया के साथ भी जुड़ जाएगा।
- 6G का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी पर्यावरण, लोगों और वस्तुओं को समझने की क्षमता होगी।

6जी नेटवर्क क्या है?

6G, दूरसंचार में छठी पीढ़ी का मानक है। यह वर्तमान में वायरलेस संचार प्रौद्योगिकियों के विकास के अधीन है जो सेलुलर डेटा नेटवर्क का समर्थन करती हैं। यह 5G नेटवर्क का नियोजित उत्तराधिकारी है। यह नेटवर्क संभवतः ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क होगा। इसमें सेवा क्षेत्र को छोटे-छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेल कहते हैं। Nokia, Ericsson, Samsung, Huawei, Xiaomi, LG और Apple जैसी कंपनियों के साथ-साथ चीन, जापान और सिंगापुर जैसे देशों ने 6G नेटवर्क विकसित करने में रुचि दिखाई है।

इस नेटवर्क का महत्व:

6G नेटवर्क अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में और भी अधिक विविधता प्रदर्शित करने की संभावना रखते हैं। इसके आभासी और संवर्धित वास्तविकता (वीआर/एआर), व्यापक खुफिया, सर्वव्यापी तत्काल संचार, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसे मौजूदा मोबाइल उपयोग परिदृश्यों से परे अनुप्रयोगों का समर्थन करने की उम्मीद है।

वर्तमान विकास:

सिंगापुर के नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और जापान के ओसाका विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से 2020 में घोषणा की कि, उन्होंने टेराहर्ट्ज़ (THz) तरंगों के लिए एक चिप विकसित की है, जिसका उपयोग 6G तकनीक में किया जा सकता है।

चीन ने 6 नवंबर, 2020 को लॉन्ग मार्च 6 वाहन रॉकेट का उपयोग करके कक्षा में 6 जी प्रौद्योगिकी के लिए उम्मीदवारों के साथ एक प्रयोगात्मक परीक्षण उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस उपग्रह को "अंतरिक्ष में टेराहर्ट्ज़ (THz) संचार प्रौद्योगिकी को सत्यापित करने" के लिए लॉन्च किया गया था।

8. इसरो निजी भागीदारी के साथ एक एसएसएलवी विकसित कर रहा है:

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) निजी भागीदारी के साथ एक लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) विकसित करने की प्रक्रिया में है। इस उपग्रह को 2022 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा।



प्रमुख बातें:

- एसएसएलवी 500 किलोमीटर की प्लेनर कक्षा में 500 किलोग्राम की पेलोड क्षमता प्रदान करेगा।
- एसएसएलवी का विकास अंतिम चरण में है।
- एसएसएलवी की पहली विकासात्मक उड़ान 2022 की पहली तिमाही के दौरान लॉन्च करने का लक्ष्य है।
- सरकार ने इस परियोजना को विकसित करने के लिए 169 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसमें वाहन प्रणालियों की योग्यता और विकास के साथ-साथ तीन विकास उड़ानों, एसएसएलवी-डी1, एसएसएलवी-डी2 और एसएसएलवी-डी3 द्वारा उड़ान प्रदर्शन शामिल हैं।

निजी क्षेत्र का योगदान:

निजी उद्योग एसएसएलवी विकास परियोजना के लिए हार्डवेयर और संरचनाओं को साकार करने में मदद करेंगे जिनमें शामिल हैं:

ठोस मोटर मामले

नोजल सब-सिस्टम

ठोस मोटर्स की ढलाई के लिए खराद का धुरा

अंतर-चरण संरचनाएं

एक्चुएटर मोटर्स और

निजी उद्योग के माध्यम से फिक्स्चर लिए जायेंगे।

लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी):

एसएसएलवी एक छोटा-लिफ्ट लॉन्च वाहन है, जिसमें 600 किलोग्राम कम पृथ्वी की कक्षा (500 किमी पर) या 300 किलोग्राम सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा (500 किमी) तक पहुंचाने की पेलोड क्षमता है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित किया जा रहा है। एसएसएलवी में कई कक्षीय ड्रॉप-ऑफ का समर्थन करने की क्षमता है। इस यान का डिजाइन 21 दिसंबर, 2018 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), थुंबा में पूरा किया गया था।

इस वाहन का उद्देश्य:

एसएसएलवी को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) की तुलना में कम कीमत और उच्च प्रक्षेपण दर पर व्यावसायिक रूप से छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है।